

प्रेषक,

आलोक कुमार वर्मा,
अपर सचिव एवं अपर विधि परामर्शी
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

श्री विजय के० जैन,
अधिवक्ता,
145, इन्जीनियर्स इस्टेट,
21, आई पी, एक्सटेंशन
नई दिल्ली ।

न्याय अनुभाग-1

देहरादून दिनांक 24 मई, 2007

विषय- माननीय उच्चतम न्यायालय में उत्तराखण्ड राज्य की ओर से पैरवी/बहस किये जाने हेतु एडवोकेट ऑन रिकार्ड के रूप में आवद्ध किया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन ने सम्मक विचारोपशान्त माननीय उच्चतम न्यायालय में उत्तराखण्ड राज्य का पक्ष प्रस्तुत करने के लिये आपको एडवोकेट ऑन रिकार्ड के रूप में शासनादेश जारी होने की तिथि से अग्रिम आदेशों तक आवद्ध किये जाने का निर्णय लिया है ।

3. उक्त आवद्धता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि यह किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है ।

4. आपको उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-128-एक(6)/छत्तीस(1)/न्याय0 अनु० /2005 दिनांक 12-9-2005 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा निर्धारित फीस अनुमन्य होगी ।

5. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि यदि सहमत हों तो कृपया अपनी लिखित सहमति उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव

संख्या-247 / XXXV(1)/2007-15जी/2000 तदुद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून ।
- 2- महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड, नैनीताल ।
- 3- महासचिव, मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली ।
- 4- महानिवक्ता, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल ।
- 5- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
- 6- अपर मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
- 7- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
- 8- विशेष कार्यधिकारी मुख्यमंत्री को मा० मुख्यमंत्री जी के सूचनार्थ ।
- 9- सुश्री रचना श्रीवास्तव, अपर महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड शासन, 39 न्यू लायर्स चैम्बर, भगवान दास रोड नई दिल्ली ।
- 10- इरला चैक अनुभाग/गार्ड फाईल N-1-C ।

आज्ञा से,



(एम० एम० सेमवाल)
अनु सचिव ।